[2017] 3 एस.सी.आर. 312

सीनी नैनार मोहम्मद

बनाम

पुलिस उपाधीक्षक द्वारा राज्य प्रतिनिधि

(2012 की आपराधिक अपील संख्या 498)

27 अप्रैल, 2017

[पिनाकी चंद्र घोष और आर.एफ. नरीमन, जेजे.]

आतंकवादी और विघटनकारी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1987- 5.20ए- अपराध का संज्ञान मंजूरी देने वाले प्राधिकारी की पूर्व मंजूरी- तथ्यों का अनुपालन, किसी व्यक्ति पर अपीलकर्ताओं ने हथियारों से हमला किया, जिसके परिणामस्वरूप उसकी मृत्यु हो गई- अपीलकर्ताओं को धारा के तहत दोषसिद्धि। 1208 आर/डब्ल्यू एसएस. 302,147,148 व 149 आईपीसी व एस.एस. टीएडीए के 3(2), (3), (4) और नीचे की अदालतों द्वारा आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई- अपील पर, आयोजित: धारा 20-ए(1) को यह इंगित करके समझा जाना चाहिए कि सक्षम प्राधिकारी से पूर्व अनुमोदन अनिवार्य है टीएडीए के तहत दंडनीय अपराध का संज्ञान लेना - हालांकि, मंजूरी देने वाले प्राधिकारी को यह ध्यान में रखना होगा कि ऐसे प्रावधानों के आवेदन के लिए सख्त व्याख्या की आवश्यकता होती है और इसका अनुपालन न करने से मामले में पूरी कार्यवाही खराब हो सकती है- तथ्यों पर, प्रावधानों का पर्याप्त अनुपालन नहीं हुआ था धारा 204 की धारा 204 की मंजूरी देने वाले प्राधिकारी ने प्रासंगिक दस्तावेजों का पालन किए बिना मंजूरी का आदेश जारी कर दिया, मंजूरी यंत्रवत् दी गई, बिना दिमाग लगाए दो आरोपियों की स्वीकारोक्ति अनैच्छिक थी और एक-दूसरे के साथ विरोधाभासी थी - मंजूरी देने वाले प्राधिकारी के

पास यह दिखाने के लिए आवश्यक सामग्री नहीं थी कि मृतक की मौत का कथित कृत्य बड़े पैमाने पर जनता के मन में आतंक पैदा करने के इरादे से किया गया था, इस प्रकार, पुलिस अधीक्षक और आईजी सीबीआई द्वारा दी गई मंजूरी निर्धारित आवश्यकताओं के अनुपालन के अभाव में पूरी तरह से अमान्य है। 20-ए-अवैध मंजूरी आदेश के परिणामस्वरूप, टाडा अधिनियम के तहत अभियोजन के लिए आपराधिक कार्यवाही पूरी तरह से टाडा अदालत द्वारा पारित दोषसिद्धि के आदेश को रद्द कर दिया गया और अलग रख दिया गया।

प्रमाण:

परीक्षण पहचान परेड - की विश्वसनीयता जब अभियुक्त को पहले ही समाचार पत्र के माध्यम से देखा जा चुका हो और अभियोजन पक्ष के गवाह ने कभी भी अभियुक्त की पहचान के लिए नहीं बुलाया- अभिनिर्धारित: परीक्षण पहचान परेड एक तमाशा था क्योंकि आरोपियों की तस्वीरें अखबार में छपने के बाद पहचान परेड नहीं की जानी चाहिए थी, जो कि बहुत कमजोर साक्ष्य है।

अभियुक्त के इकबालिया बयान - की विश्वसनीयता कायम- अभिनिर्धारित: गैर-स्वैच्छिक कबूलनामा तथ्यों पर दोषसिद्धि का आधार नहीं बन सकता। अभियुक्तों की स्वीकारोक्ति अनैच्छिक है क्योंकि उन्हें तुरंत ही सीबीआई की कड़ी सुरक्षा में हिरासत में ले लिया गया था, जिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता।

न्यायालय ने अपील स्वीकार करते हुए अभिनिर्धारित किया :-

1. मौजूदा मामले में पूरी कार्यवाही दूषित थी। इसलिए, नामित न्यायालय द्वारा पारित दोषसिद्धि और सजा के आदेश को किया जाता है और रद्द कर दिया जाता है। [पैरा 28][334-बी]

2.1 पीडब्लू-28 आईजी द्वारा 16.09.1997 को दी गई मंजूरी, केवल 3.04.1997 को दर्ज किए गए ए-1 के कबूलनामे को संदर्भित करती है, लेकिन इसमें ए-6 के कबूलनामे का उल्लेख नहीं है जो 25.10.1994 को दर्ज किया गया था। यह एकमात्र दस्तावेज़ था जिससे पता चला कि ए-6 ने तमिलनाडु में बड़े पैमाने पर जनता के मन में आतंक पैदा करने के इरादे से ए-1 को ए-5 को 'आर' की हत्या करने की सलाह दी थी। इसलिए, ए-6 का इकबालिया बयान ही एकमात्र दस्तावेज है जो टाडा अधिनियम की धारा 3 के तहत आवश्यक आतंक पैदा करने के इरादे को संदर्भित करता है। किसी अन्य सामग्री या किसी अन्य गवाह ने जनता के मन में आतंक पैदा करने के इरादे से हत्या करने के आरोपी के इरादे के बारे में बात नहीं की, जो टाडा अधिनियम को लागू करने के लिए मुख्य घटक है। दुर्भाग्य से, उक्त दस्तावेज़ को मंजूरी आदेश में मंजूरी प्राधिकारी द्वारा न तो संदर्भित किया गया था और न ही उस पर भरोसा किया गया था। [पैरा 7] [320-एफ-एच]

2.2 ए-1 की स्वीकारोक्ति ए-6 की स्वीकारोक्ति से पूरी तरह विरोधाभासी है। तथ्यों से ऐसा प्रतीत होता है कि जांच अधिकारी ने मंजूरी प्राधिकारी के समक्ष इसे न रखकर महत्वपूर्ण दस्तावेज को दबा दिया। टाडा अदालत ने आरोपी को टाडा अधिनियम के तहत ए-6 के कबूलनामे के आधार पर दोषी ठहराया, न कि किसी अन्य सामग्री के आधार पर। दूसरी बात जो नोट की गई है वह यह है कि मंजूरी प्राधिकारी-पीडब्लू-28 ने अपने बयान में स्वीकार किया कि वह तमिल नहीं जानता था और उसने उन सभी रिकॉर्डों को नहीं देखा जो तमिल में थे। इसलिए, यह स्पष्ट है कि मंजूरी देने वाले प्राधिकारी ने पूरी तरह से अपना दिमाग नहीं लगाया और इस पर विचार करने के बाद ही मंजूरी दी। दस्तावेज़ जो अंग्रेजी में थे। इसलिए, यह स्वीकार किया जाता है कि मंजूरी देने वाले प्राधिकारी ने प्रासंगिक दस्तावेजों पर गौर किए बिना मंजूरी का आदेश

जारी कर दिया और इस प्रकार यह स्वीकार किया जाना चाहिए कि मंजूरी यांत्रिक रूप से दी गई थी। [पैरा 8] [321-ए-सी]

2.3 टाडा अधिनियम के तहत संज्ञान लेने के लिए मंजूरी देते समय मंजूरी देने वाले प्राधिकारी द्वारा विवेक का उपयोग न करने और अधिनियम के उद्देश्य को कमजोर करने के लिए टाडा की धारा 20ए के प्रावधानों का पर्याप्त अनुपालन नहीं किया जा सकता है। यह प्रासंगिक प्रावधान 1993 के अधिनियम 43 द्वारा डाला गया था जो 23.05.1993 को लागू हुआ था जो कि अपराध के घटित होने की तारीख से पहले यानी 10.10.1994 को तत्काल अपील में विवादित था, जो यह स्पष्ट करता है कि धारा 20-ए (1) का तात्पर्य यह इंगित करके किया जाना चाहिए कि TADA के तहत दंडनीय अपराध का संज्ञान लेने के लिए सक्षम प्राधिकारी से पूर्व अनुमोदन अनिवार्य है। हालाँकि, मंजूरी देने वाले प्राधिकारी को यह हमेशा ध्यान में रखना होगा कि ऐसे प्रावधानों को लागू करना जो दंडात्मक कानूनों का हिस्सा हैं, उन्हें सख्त व्याख्या की आवश्यकता होती है और संज्ञान लेने से पहले मंजूरी की अनिवार्य आवश्यकता का पालन करने में विफलता, जैसा कि टीएडीए में उल्लिखित है, उल्लंघन कर सकती है। मामले की पूरी कार्यवाही. [पैरा 10][321-ई-जी]

हुसैन घडियाली उर्फ एम.एच.जी.ए. शेख और अन्य बनाम गुजरात राज्य (2014) 8 एससीसी 425: [2014] 9 एससीआर 364- संदर्भित।

2.4 पूर्व अनुमोदन प्राप्त करने के लिए पीडब्लू-24 द्वारा पीडब्लू-26 को दी गई मांग का सावधानीपूर्वक अध्ययन करने से पता चलता है कि 10.10.1994 को एक भी हत्या का उल्लेख किया गया था, लेकिन जनता के मन में आतंक और दहशत पैदा करने के इरादे से हत्या का कोई कृत्य नहीं किया गया था। जो कि टाडा अधिनियम के

तहत अपराध का मुख्य घटक है, का उल्लेख किया गया था। मदुरै में हिंदू मंदिर के पास मस्जिद के निर्माण पर हिंदुओं द्वारा उठाई गई आपत्तियों से संबंधित इस हत्या से पहले की घटना का उल्लेख पीडब्लू-24 के बयान में किया गया था, जिसे कहीं भी हत्या के कृत्य से जोड़ा या संदर्भित नहीं किया जा सका। माना जाता है कि, उनके बयान के अनुसार, 19.10.1994 तक, किसी ने भी कोई शिकायत नहीं दी कि घटना के स्थान पर कोई हंगामा या हिंसा हुई थी, जिसके परिणामस्वरूप आईपीसी के तहत मामले को टाडा के तहत प्रथम दृष्टया मामला माना गया, जिसके लिए पूर्व अनुमति मांगी गई, जो यदि दिया गया, तो कानून की नजर में बुरा होगा। [पैरा 12] [323-ई-जी]

2.5 टाडा की धारा 20-ए (2) के तहत मंजूरी प्राधिकारी, ले. तत्काल मामले में पीडब्लू 28-आईजी, सीबीआई ने अनुमति आदेश के माध्यम से 16.09.1997 को टाडा के तहत मामला दर्ज करने की अनुमति दी थी। मंजूरी देने वाले प्राधिकारी के पास यह दिखाने के लिए आवश्यक सामग्री नहीं थी कि मृतक की मौत का कथित कार्य बड़े पैमाने पर जनता के मन में आतंक पैदा करने के इरादे से किया गया था। यदि लोगों के मन में ऐसी कोई दहशत होती, तो मृतक की मौत के परिणामस्वरूप घटना स्थल के आसपास के विभिन्न वर्गों के लोगों के बीच सौहार्द पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता। हालाँकि, लोगों के मन में दहशत पैदा करने या समाज के किसी भी वर्ग के बीच सद्भाव पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की कोई घटना सामने नहीं आई। किसी व्यक्ति की मौत का कथित कृत्य केवल आरोपी-अपीलकर्ताओं द्वारा मृतक पर हथियारों से हमला था, जिसने बाद में चोटों के कारण दम तोड़ दिया। [पैरा 13] [323-एच: 324-सी-डी]

2.6 ए-6 के संबंध में TADA की धारा 20-ए (2) के तहत मंजूरी पीडब्लू-29 द्वारा 16.09.1998 को दी गई थी, जिसमें उसके साथ-साथ जांच में समय लगने के कारण देरी हुई थी। बताए गए कारणों से यह भी गैरकानूनी है। इसके अलावा, पीडब्लू-

30 की जिरह भी दिमाग के गैर-प्रयोग को प्रतिबिंबित कर रही है जब आरोपी-अपीलकर्ताओं के अलुम्मा संगठन के साथ संबंध के बारे में विशेष रूप से बताने के बाद, उसके द्वारा यह दर्शाया गया था कि उस संगठन के थे उसने आरोपी को दिखाने के लिए कोई सबूत या दस्तावेज एकत्र नहीं किया था। इन गवाहों के बयानों से उक्त प्रतिबंध साबित नहीं हुए हैं। [पैरा 14][324-डी-एफ]

महाराष्ट्र राज्य बनाम महेश और जैन (2013) 8 एससीसी 119: [2013] 3 एससीआर 850; कूथा पेरुमल बनाम राज्य (2011) 1 एससीसी 491: [2010] 14 एससीआर 864 का उल्लेख किया गया है।

2.7 इस न्यायालय के लिए, विधायी प्रयास के अभाव में, यह परिभाषित करने के लिए एक राय प्रदान करना खतरनाक होगा कि कोई गतिविधि आतंकवादी गतिविधि की परिभाषा के अंतर्गत आती है या नहीं। आख़िरकार किसी भी क़ानून को लागू करने के पीछे विधायी मंशा प्रबल होगी। [पैरा 18] [327-ए-बी]

गिरधारी परमानंद वधवा बनाम महाराष्ट्र राज्य (1996) 11 एससीसी 179: [1996] 6 पूरक। एससीआर 631-भरोसेमंद पर।

कल्पनाथ राय बनाम राज्य (सीबीआई के माध्यम से) (1997) 8 एससीसी 732; करतार सिंह बनाम पंजाब राज्य 1994 (3) एससीसी 569: [1994] 2 एससीआर 375, हितेंद्र विशमी ठाकुर और अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य (1994) 4 एससीसी 602: [1994] 1 पूरक एससीआर 360– संदर्भित।

2.8 प्रतिवादी लोगों के मन में आतंक पैदा करने या उन पर आतंक का हमला करने के इरादे के अभाव में टाडा के प्रावधानों के तहत मामला नहीं बना सकता है। इसलिए, तत्काल मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में पुलिस अधीक्षक-पीडब्लू-26 और

आईजी, सीबीआई-पीडब्लू-28 द्वारा दी गई मंजूरी, टाडा की धारा 20-ए के तहत निर्धारित आवश्यकताओं के अनुपालन के अभाव में पूरी तरह से अमान्य थी। अवैध मंजूरी आदेश के परिणामस्वरूप टाडा अधिनियम के तहत अभियोजन की आपराधिक कार्यवाही पूरी तरह से ख़राब हो गई है। टाडा अधिनियम के तहत अदालत ने मामले का संज्ञान लेने में घोर गलती की। [पैरा 19,20] [328-ई-एफ: 329-जी]

अशरफखान उर्फ बाबू मुन्नेखान पठान और अन्य बनाम गुजरात राज्य (2012) 11 एससीसी 606: [2012] 12 एससीआर 1033 का उल्लेख किया गया है।

2.9 यद्यपि नामित न्यायालय द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण को पूरी तरह से स्वीकार करने में थोड़ी कठिनाई है, क्योंकि यह कई उल्लेखनीय तथ्यों से उत्पन्न होता है, लेकिन इस बात पर विवाद नहीं किया जा सकता है कि मृतक को उसके घर के प्रवेश द्वार पर मार दिया गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट, जिसे डॉक्टर द्वारा विधिवत प्रमाणित किया गया था, में यह भी उल्लेख किया गया है कि मृत्यु का कारण 10.10.1994 को सुबह 5 बजे के आसपास मृतक को कई कट और चाकू से लगी चोटों के कारण सदमा और रक्तस्राव था। आरोपी की पहचान के लिए पीडब्लू-1 को कभी नहीं बुलाया गया। [पैरा 22][330-बी-सी]

2.10 जहाँ तक परीक्षण पहचान परेड की विश्वसनीयता का सवाल है, जब स्वीकार किया गया कि अभियुक्तों को पहले ही समाचार पत्र के माध्यम से देखा गया था, तो पहचान परेड एक दिखावा था क्योंकि अभियुक्तों की तस्वीरें समाचार पत्र में प्रकाशित होने के बाद, पहचान परेड जो बहुत कमजोर है सबूत का टुकड़ा आयोजित नहीं किया जाना चाहिए था! [पैरा 23, 24] [330-डी: 331-ए-बी]

सुरेश चंद्र बाहरी बनाम बिहार राज्य (1995) पूरक 1 एससीसी 80: [1994] 1 पूरक एससीआर 483 का उल्लेख किया गया है।

2.11 ए-1 और ए-6 के इकबालिया बयान स्वैच्छिक नहीं थे, जैसा कि सामग्री से पता चलता है क्योंकि उन बयानों को स्वतंत्र माहौल में दर्ज नहीं किया गया था, उन्हें सीबीआई की उच्च सुरक्षा की तत्काल हिरासत में ले लिया गया था और एक गैर-स्वैच्छिक बयान नहीं बनाया जा सकता है दोषसिद्धि का आधार, इसके अलावा, उक्त स्वीकारोक्ति पर भरोसा नहीं किया जा सकता क्योंकि वे एक-दूसरे के विरोधाभासी थे। [पैरा 9, 26] [321-डी; 333-सी]

राज्य (एनसीटी दिल्ली) बनाम नवजोत संधू (2005) 11 एससीसी 600: [2005] 2 पूरक। एससीआर 79-संदर्भित।

केस कानून संदर्भ

[2014] 9 एससीआर 364	संदर्भित	पैरा 10
[1997] 8 एससीसी 732	संदर्भित	पैरा 11
[2013] 3 एससीआर 850	संदर्भित	पैरा 14
[2010] 14 एससीआर 864	संदर्भित	पैरा 14
[1994] 2 एससीआर 375	संदर्भित	पैरा 16
[1996] 6 पूरक एससीआर 631	भरोसा किया	पैरा 17
[1994] 1 पूरक एससीआर 360	संदर्भित	पैरा 18
[2012] 12 एससीआर 1033	संदर्भित	पैरा 19
[1994] 1 पूरक। एससीआर 483	संदर्भित	पैरा 23
[2005] 2 पूरक। एससीआर 79	संदर्भित	पैरा 25

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार: आपराधिक अपील संख्या 498/2012।

तिरुनेलवेई में 1997 के टाडा केस नंबर । में टाडा मामलों के लिए नामित न्यायाधीश, के निर्णय और आदेश दिनांक 08.09.2011 से।

साथ

2012 का आपराधिक संख्या 867।

एम. करपगा विनायगम, सलमान खुर्शीद, वरिष्ठ वकील, के.के. मणि, एस. अंसार मोहम्मद, श्रीमती टी. अर्चना, एस.आई. अब्दुल कलाम बगदुर शा, सैयद महबूब, डॉ. एस.के. सैमी, टी.आर.बी शिवकुमार, एनटोनी जुलीयन, पी.के. डे, राजीव नंदा, टी.ए. खान, श्रेयसी चक्रवर्ती, मनीष, सुश्री शिल्पी डे, सुश्री रीना राय, मुकेश कुमार मरोरिया, अधिवक्ता उपस्थित पक्षों के लिए।

न्यायालय का निर्णय पिनाकी चंद्र घोष, जे. सुनाया गया।

1. ये दो अपीलें टाडा केस नंबर 1/1997 में टाडा मामलों के लिए नामित न्यायाधीश की अदालत, तिरुनेलवेली द्वारा पारित 8 सितंबर, 2011 के फैसले और आदेश के खिलाफ निर्देशित हैं, जिसके तहत विद्वान नामित न्यायाधीश ने अपीलकर्ताओं को भारतीय दंड संहिता, 1860 (इसके बाद "आईपीसी" के रूप में संदर्भित) की धारा 302, 147, 148 और 149 के साथ पठित धारा 120 (बी) और धारा 3(2), 3(3) के तहत दंडनीय अपराधों के लिए दोषी पाया गया और आतंकवादी और विघटनकारी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1987 (संक्षेप में "टाडा") की धारा 3(4) के तहत उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई।

2. टाडा मामलों के निर्णय के लिए नामित न्यायालय के विद्वान विशेष न्यायाधीश द्वारा मामले के तथ्यों पर विस्तृत चर्चा की गई है। इसलिए, हमें उस संपूर्ण तथ्यात्मक पृष्ठभूमि को दोहराने की आवश्यकता नहीं है जिसमें अपीलकर्ताओं पर

मुकदमा चलाया गया, उन्हें दोषी पाया गया और सजा सुनाई गई, सिवाय इसके कि जहां ऐसा करना बिल्कुल जरूरी हो। इस मामले में छह आरोपी हैं, साहुल हमीद (ए-1), राजा हुसैन (ए-2), जुबेर (ए-3), जाकिर हुसैन (ए-4), अज़ीज़ (ए-5) और सीनी नैनार मोहम्मद (ए-6), 10 अक्टूबर, 1994 को सुबह लगभग 06:30 बजे, ए-1 से ए-6 अपने बीच रची गई साजिश के अनुसरण में, एक राजगोपालन (मृतक के बाद से) के घर गए, जो हिंदू मुन्नानी एसोसिएशन के अध्यक्ष थे, उसे मारने के मकसद से. घटना से एक दिन पहले ए-6 सीनी नैनार मोहम्मद ने अपने भाई राजा हुसैन (ए-2) को राजगोपालन की हत्या का काम पूरा करने के बाद उससे मिलने की सलाह दी थी. जब राजगोपालन, अखबार के उप-एजेंट सरवनम (पीडब्लू-3) से अखबार लेने के बाद, अपने घर पर पूर्व की ओर मुंह करके अखबार देख रहे थे, आरोपी व्यक्ति राजगोपालन के बाईं ओर से आए और ए-1 ने उनकी गर्दन पकड़ ली। राजगोपालन के पीछे से ए-3 और ए-4 ने चाकू निकाले और उसके पेट पर वार कर दिया। ए-5 ने दरांती दिखाकर जनता को भाग जाने की धमकी दी और उक्त राजगोपालन पर बार-बार हमला किया और उसके बाद वे पश्चिम की ओर भाग गए। शोर सुनकर मृतक की पत्नी पीडब्लू-1 कृष्णावेणी घर से बाहर आई तो देखा कि उसका पति खून से लथपथ पड़ा हुआ था। घटना को पीडब्लू-1, पीडब्लू-3, पीडब्लू-4, पीडब्लू-5 और पीडब्लू-6 ने देखा था। पीडब्ल्यू- मैंने घटना की जानकारी बाजार थाने को दूरभाष पर दी। सूचना मिलने पर बाजार थाने के इंस्पेक्टर पीडब्लू-2 मौके पर पहुंचे और पीडब्लू-1 से पूछताछ की जिसने एक लिखित शिकायत उनको दी।

3. कानून तब लागू हुआ जब पीडब्लू-2 स्टालिन माइकल, इंस्पेक्टर मदुरै जिले के पुलिस स्टेशन थिलागर ग्राउंड में सुबह 07:30 बजे अपराध संख्या 2490/1994 में आईपीसी की धारा 147, 148 और 302 के तहत एफआईआर एक्सटेंशन पी 2 दर्ज की गई। डीजीपी के आदेश पर, मामला स्थानीय पुलिस से सीबीसीआईडी को स्थानांतरित

कर दिया गया और श्री राजगोपाल, डीएसपी (पीडब्लू-24) ने जांच की, घटनास्थल पर गए, गवाहों से पूछताछ की और उनके बयान दर्ज किए। चूंकि पीडब्लू-24 के पास अतिरिक्त प्रभार था, इसलिए वह जांच का कार्य पूरा नहीं कर सका और आगे की जांच श्री जोन्स, डीएसपी (पीडब्लू-30) द्वारा की गई और पुलिस अधीक्षक (पीडब्लू-26) से पूर्व अनुमोदन प्राप्त करने के बाद, मामला दर्ज किया गया। टाडा के तहत मामला मामले के रिकॉर्ड टाडा मामलों के लिए विद्वान नामित न्यायाधीश को स्थानांतरित कर दिए गए और सुनवाई के बाद, विद्वान नामित न्यायाधीश ने अपने फैसले और आदेश दिनांक 08.09.2011 द्वारा टाडा मामले संख्या 1/1997 में सभी आरोपियों को यह कहते हुए दोषी ठहराया कि अभियोजन पक्ष ने साबित कर दिया है A-1 से A-6 के विरुद्ध पहला आरोप। A-1 से A-5 को TADA की धारा 3(2) के साथ पठित धारा 3(1) के साथ IPC की धारा 149 के तहत दोषी ठहराया गया और आजीवन कारावास और प्रत्येक को 10,000/- रुपये का जुर्माना भरने की सजा सुनाई गई। जुर्माना अदा न करने पर 1 वर्ष का कठोर कारावास भुगतना होगा। हालाँकि, A-6 को TADA की धारा 3(2) के साथ पठित 3(1) के साथ IPC की धारा 109 और TADA की धारा 3(4) के तहत दोषी ठहराया गया और आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई और जुर्माना भी भरना पड़ा। 5,000/- रुपये और जुर्माना न देने पर 1 वर्ष का कठोर कारावास भुगतना होगा। हालाँकि, सभी सजाएँ एक साथ चलने का निर्देश दिया गया था। इसलिए, टीएडीए की धारा 19 के तहत वर्तमान अपीलें सुप्रीम कोर्ट (आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार का विस्तार) अधिनियम, 1970 के साथ पढ़ी जाती हैं। 2012 की आपराधिक अपील संख्या 498 ए-6 द्वारा दायर की गई है, जबकि 2012 की आपराधिक अपील संख्या 867 दायर की गई है। ए-1 से ए-5 तक दायर किया गया।

4. हमने आक्षेपित निर्णय और रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री का सावधानीपूर्वक अध्ययन किया है और गवाहों की गवाही और प्रस्तुत किए गए अन्य प्रासंगिक साक्ष्यों

की भी सावधानीपूर्वक जांच की है। चूंकि नामित द्वारा पारित किसी भी निर्णय के खिलाफ अपीलीय क्षेत्राधिकार टाडा मामलों की अदालत केवल इसी अदालत में है, हम इस पर विचार करेंगे। वर्तमान मामले की विशिष्ट परिस्थितियों पर उचित रूप से चर्चा करें हमारे सामने प्रासंगिक मुद्दा विचाराधीन है।

5. सबसे पहला मुद्दा जो दबाए जाने पर हमारे संकल्प पर भारी पड़ता है। अभियुक्त-अपीलकर्ताओं के लिए विद्वान वरिष्ठ वकील द्वारा यह बताया गया है कि क्या वर्तमान मामले में अनुमोदन को पर्याप्त अनुपालन कहा जा सकता है टाडा की धारा 20-ए के प्रावधान जो इस प्रकार हैं:-

> "20-ए अपराध का संज्ञान (1) संहिता में किसी भी बात के बावजूद, इस अधिनियम के तहत अपराध के घटित होने के बारे में कोई भी जानकारी जिला पुलिस अधीक्षक की पूर्व अनुमति के बिना पुलिस द्वारा दर्ज नहीं की जाएगी।
>
> (2) कोई भी अदालत पुलिस महानिरीक्षक, या जैसा भी मामला हो, पुलिस आयुक्त की पूर्व मंजूरी के बिना इस अधिनियम के तहत किसी भी अपराध का संज्ञान नहीं लेगी।"

6. हमने इस तथ्य पर विचार किया है कि जांच के बाद, सीबीआई के पीडब्लू-30 डीएसपी ने 13 सितंबर, 1997 को पीडब्लू-28 आईजी से संपर्क किया और टाडा अधिनियम के तहत अपराधों के लिए ए-1 से ए-5 के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी मांगी। पीडब्लू-28 ने 16 सितंबर, 1997 को टाडा अधिनियम के तहत ए-1 से ए-5 के खिलाफ अभियोजन के लिए मंजूरी (एक्सटी.पी-46) दी। पीडब्लू-28, आईजी द्वारा यह कहा गया है कि उन्होंने पीडब्लू-30 द्वारा रखे गए सभी रिकॉर्डों का अवलोकन किया, जिसमें जांच रिपोर्ट, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, चश्मदीद गवाहों के 164 बयान और

अन्य गवाहों के 161 बयान शामिल थे, ए-1 और अन्य सामग्रियों की स्वीकारोक्ति और टाडा अधिनियम, 1987 की धारा 3 के तहत ए-1 से ए-5 के खिलाफ अभियोजन की मंजूरी दी गई। यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि जांच के दौरान, ए-6 (एक्सटी.पी-43) की स्वीकारोक्ति दिनांक 25.10.1994 को पीडब्लू-24 डीएसपी, सीबीसीआई, डीएसपी द्वारा दी गई मांग के आधार पर पीडब्लू-26 द्वारा दर्ज किया गया था। बाद में मामला जुलाई, 1996 में सीबीआई को स्थानांतरित कर दिया गया और स्थानांतरण पर, पीडब्लू-30 सीबीआई, डीएसपी ने 17.07.1996 को जांच शुरू की।

7. हमने यह भी नोट किया है कि पीडब्ल्यू-28 आईजी द्वारा 16.09.1997 को दी गई मंजूरी (प्रदर्श पी-46), केवल 03.04.1997 को दर्ज किए गए ए-1 के कबूलनामे (प्रदर्श पी-41) को संदर्भित करती है, लेकिन ऐसा नहीं है ए-6 (प्रदर्श पी-43) के कबूलनामे का संदर्भ लें जो 25.10.1994 को दर्ज किया गया था। यह एकमात्र दस्तावेज़ था जिससे पता चला कि ए-6 ने तमिलनाडु में बड़े पैमाने पर जनता के मन में आतंक पैदा करने के इरादे से ए-1 को ए-5 को राजगोपालन की हत्या करने की सलाह दी थी। इसलिए, ए-6 (प्रदर्श पी-43) का इकबालिया बयान ही एकमात्र दस्तावेज है जो टाडा अधिनियम की धारा 3 के तहत आवश्यक आतंक पैदा करने के इरादे को संदर्भित करता है। कोई अन्य सामग्री या कोई अन्य गवाह अभियुक्त के अपराध करने के इरादे के बारे में नहीं बताता है। जनता के मन में दहशत पैदा करने के इरादे से की गई हत्या टाडा अधिनियम लागू करने का मुख्य घटक। दुर्भाग्य से, कहा गया दस्तावेज़ (प्रदर्श पी-41) का न तो संदर्भ दिया गया है और न ही उस मंजूरी आदेश में मंजूरी प्राधिकारी (प्रदर्श पी-46) पर भरोसा किया गया है।

8. हमने यह भी देखा है कि ए-1 (प्रदर्श पी-41) का इकबालिया बयान ए-6 (प्रदर्श पी-43) के कबूलनामे से पूरी तरह विरोधाभासी है। तथ्यों से ऐसा प्रतीत होता है कि जांच अधिकारी ने मंजूरी प्राधिकारी के समक्ष इसे न रखकर महत्वपूर्ण दस्तावेज को

दबा दिया। हमने आगे देखा है कि टाडा अदालत ने आरोपी को टाडा अधिनियम के तहत ए-6 की स्वीकारोक्ति के आधार पर दोषी ठहराया, न कि किसी अन्य सामग्री के आधार पर। दूसरा बिंदु जो हमने नोट किया है वह यह है कि मंजूरी प्राधिकारी (पीडब्लू-28) ने अपने बयान में स्वीकार किया कि वह तमिल नहीं जानता था और उसने उन सभी रिकॉर्डों को नहीं देखा जो तमिल में थे। इसलिए, यह स्पष्ट है कि मंजूरी देने वाले प्राधिकारी ने पूरे रिकॉर्ड पर अपना दिमाग नहीं लगाया है और केवल कुछ दस्तावेजों पर विचार करने के बाद ही मंजूरी दे दी है जो अंग्रेजी में थे। इसलिए, हमें अपीलकर्ताओं के इस तर्क को स्वीकार करना होगा कि मंजूरी देने वाले प्राधिकारी ने संबंधित दस्तावेजों पर गौर किए बिना मंजूरी का आदेश जारी कर दिया और इस तरह यह स्वीकार करना होगा कि मंजूरी यांत्रिक रूप से दी गई थी।

9. ए-1 और ए-6 के इकबालिया बयान स्वैच्छिक नहीं हैं, जैसा कि हमने सामग्री से प्रमाणित किया है क्योंकि उन बयानों को स्वतंत्र माहौल में दर्ज नहीं किया गया था, जिससे इस न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देशों का उल्लंघन हुआ। इसके अलावा, उक्त स्वीकारोक्ति पर भरोसा नहीं किया जा सकता क्योंकि वे एक-दूसरे के विरोधाभासी थे।

10. हम, बिना किसी हिचकिचाहट के, इस विचार पर सहमत हैं कि इस प्रश्न का उत्तर टाडा अधिनियम के तहत संज्ञान लेने के लिए अनुमोदन प्रदान करते समय मंजूरी देने वाले प्राधिकारी द्वारा दिमाग का उपयोग न करने और अधिनियम के उद्देश्य को कमजोर करने के स्थापित सिद्धांत के लिए नकारात्मक है। यह प्रासंगिक प्रावधान 1993 के अधिनियम 43 द्वारा डाला गया था जो 23.05.1993 को लागू हुआ था जो कि अपराध के घटित होने की तारीख से पहले है, यानी 10.10.1994 को तत्काल अपील में विवादित है जो यह स्पष्ट करता है कि धारा 20-ए (1) टाडा का तात्पर्य यह दर्शाते हुए किया जाना चाहिए कि टाडा के तहत दंडनीय अपराध का संज्ञान लेने के लिए सक्षम

प्राधिकारी से पूर्व अनुमोदन अनिवार्य है। हालाँकि, मंजूरी देने वाले प्राधिकारी द्वारा यह हमेशा ध्यान में रखा जाएगा कि ऐसे प्रावधानों को लागू करना जो दंडात्मक प्रावधानों का हिस्सा हैं, उन्हें सख्त व्याख्या की आवश्यकता होती है और संज्ञान लेने से पहले मंजूरी की अनिवार्य आवश्यकता का पालन करने में विफलता, जैसा कि टाडा में उल्लिखित है, उल्लंघन कर सकती है। मामले की पूरी कार्यवाही. हाल ही में ऐसा देखने को मिला है। हुसैन के मामले में टाडा की धारा 20-ए के संबंध में इस न्यायालय द्वारा घडियाली उर्फ एम.एच.जी.ए. शेख और अन्य बनाम गुजरात राज्य, (2014) 8 एससीसी 425, पैरा 21 पर, इस प्रकार है:-

> "उपरोक्त को सावधानीपूर्वक पढ़ने से इसमें कोई संदेह नहीं रह जाता है कि प्रावधान एक गैर-अस्पष्ट खंड से शुरू होता है और नकारात्मक वाक्यांशविज्ञान में शामिल है। यह पुलिस अधीक्षक जिले की पूर्व अनुमति के बिना पुलिस द्वारा टीएडीए के तहत अपराध के कमीशन के बारे में जानकारी दर्ज करने से मना करता है।"

11. मंजूरी देने वाले प्राधिकारी के समक्ष निर्धारण के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक यह था कि किसी व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य आतंकवादी गतिविधि के दायरे में आना चाहिए और आरोपी को धारा 3(1) में परिभाषित अनुसार आतंकवादी होना चाहिए। कानून की इस स्थिति पर इस न्यायालय द्वारा कल्पनाथ राय बनाम राज्य (सीबीआई के माध्यम से), (1997) 8 एससीसी 732, के मामले में चर्चा की गई थी। इस प्रकार है:

> "34. 1993 के अधिनियम 43 द्वारा टीएडीए में उप-धारा 3(5) शामिल किया गया था जो 23-5-1993 को लागू हुआ। संविधान के अनुच्छेद 20(1) के तहत 'किसी भी व्यक्ति को किसी भी अपराध के

लिए दोषी नहीं ठहराया जाएगा। अपराध के रूप में आरोपित कृत्य के समय लागू कानून का उल्लंघन। इसलिए यह पर्याप्त नहीं है कि कोई व्यक्ति 23.5-1993 से पहले आतंकवादी गिरोह का सदस्य था।

35. उपधारा (3) में दो अभिधारणाएँ हैं। फिरत यह है कि आरोपी 23.5.1993 के बाद 'किसी आतंकवादी गिरोह या 'आतंकवादी संगठन' का सदस्य रहा हो। दूसरा यह कि उक्त गिरोह या संगठन 23.5.1993 के बाद आतंकवादी कृत्यों में शामिल रहा हो। जब तक दोनों अभिधारणाएँ एक साथ विद्यमान न हों, धारा 3(3) का प्रयोग किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध नहीं किया जा सकता।

36. आतंकवादी कृत्य को धारा 2(एच) में वही अर्थ दिया गया है जो धारा 3(1) में दिया गया है। वह उपधारा इस प्रकार है:

'3(1) जो भी कानून द्वारा स्थापित सरकार को भयभीत करने या लोगों या लोगों के किसी भी वर्ग में आतंक पैदा करने या लोगों के किसी भी वर्ग को अलग-थलग करने या लोगों के विभिन्न वर्गों के बीच सद्भाव पर प्रतिकूल प्रभाव डालने के इरादे से कोई कार्य करता है बम, डायनामाइट या अन्य विस्फोटक पदार्थ या ज्वलनशील पदार्थ या आग्नेयास्त्र या अन्य घातक हथियार या जहर या हानिकारक गैसों या अन्य रसायनों या खतरनाक प्रकृति के किसी भी अन्य पदार्थ (चाहे जैविक या अन्यथा) का उपयोग करके कार्य या वस्तु किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों की मृत्यु या चोट लगने या संपत्ति की हानि, या क्षति, या विनाश या समुदाय के जीवन के लिए आवश्यक किसी भी आपूर्ति या सेवाओं में व्यवधान उत्पन्न होने या होने की संभावना है, या

किसी व्यक्ति को हिरासत में लेता है और सरकार या किसी अन्य व्यक्ति को कोई कार्य करने के लिए मजबूर करने या उसे करने से रोकने के लिए ऐसे व्यक्ति को मारने या घायल करने की धमकी देता है, आतंकवादी कार्य करता है।

37. उप-धारा की आवश्यकताएं हैं: (1) व्यक्ति को इस तरह से कार्य करना चाहिए जिससे किसी व्यक्ति की मृत्यु या चोट लगने या किसी संपत्ति को नुकसान होने या व्यवधान उत्पन्न होने की संभावना हो। कोई आपूर्ति; (2) ऐसा कृत्य बम, डायनामाइट आदि का उपयोग करके किया जाना चाहिए था; (3) या वैकल्पिक रूप से उसे सरकार या किसी अन्य व्यक्ति को कुछ भी करने या कुछ भी करने से रोकने के लिए मजबूर करने के लिए किसी व्यक्ति को हिरासत में लेना चाहिए था और उसे मारने या घायल करने की धमकी देनी चाहिए थी।"

12. अपीलकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील श्री करपगा विनायगम ने कहा कि वर्तमान मामले में पीडब्लू-26 द्वारा टीएडीए के तहत मामले की जांच के लिए दी गई पूर्व स्वीकृति कानून की दृष्टि से खराब है क्योंकि इसे पीडब्लू-26 द्वारा प्रदान किया गया है। यंत्रवत्, बिना रिकॉर्ड देखे और बिना अपनी संतुष्टि दर्ज किए। पूर्व अनुमोदन प्राप्त करने के लिए पीडब्लू-24 द्वारा पीडब्लू-26 को दी गई मांग का सावधानीपूर्वक अवलोकन (प्रदर्श पी-35) से पता चलता है कि 10.10.1994 को एक भी हत्या का उल्लेख किया गया था, लेकिन आतंक और आतंक पैदा करने के इरादे से हत्या का कोई कृत्य नहीं किया गया था। जनता के मन में, जो टाडा अधिनियम के तहत अपराध का मुख्य घटक है, का उल्लेख किया गया था। मदुरै में हिंदू मंदिर के पास मस्जिद के निर्माण पर हिंदुओं द्वारा उठाई गई आपत्तियों से संबंधित इस हत्या से

पहले की घटना का उल्लेख पीडब्लू-24 के बयान में किया गया था, जिसे कहीं भी हत्या के कृत्य से जोड़ा या संदर्भित नहीं किया जा सका। माना जाता है कि, उनके बयान के अनुसार, 19.10.1994 तक, किसी ने भी कोई शिकायत नहीं दी कि घटना के स्थान पर कोई हंगामा या हिंसा हुई थी, जिसके परिणामस्वरूप आईपीसी के तहत मामले को टाडा के तहत प्रथम दृष्टया मामला माना गया, जिसके लिए पूर्व अनुमति मांगी गई, जो यदि दिया गया, तो कानून की नजर में बुरा होगा।

13. हमने यह भी देखा है कि मंजूरी प्राधिकारी के अधीन वर्तमान मामले में टाडा की धारा 20-ए (2), यानी पीडब्लू 28-आईजी, सी.बी.आई. 16.09.1997 को टीएडीए के तहत मामला दर्ज करने की अनुमति दी गई। अनुमति आदेश प्रदर्श पी-46 है और अपने बयान में पीडब्ल्यू-28 ने कहा है कि

''...मैंने टाडा नियमों को बहुत सावधानी से सत्यापित किया। उक्त दस्तावेजों को पढ़ने के बाद जब मैं संतुष्ट हो गया कि टाडा अधिनियम के तहत शाहुल हमीद, राजा हुसैन, सुबैर, जहीर हुसैन और अजीज उर्फ अब्दुल अजीज के खिलाफ मामला दर्ज करने के लिए पर्याप्त सबूत हैं, तो मैंने अनुमति देने के आदेश जारी किए। टाडा अधिनियम की धारा 3 के तहत मामला दर्ज करें..."। हम सीधे तौर पर देख सकते हैं कि मंजूरी देने वाले प्राधिकारी के पास यह दिखाने के लिए आवश्यक सामग्री नहीं थी कि मृतक की मौत का कथित कार्य आतंक पैदा करने के इरादे से किया गया था। यदि लोगों के मन में ऐसा कोई भय होता, तो मृतक की मृत्यु के परिणामस्वरूप उस स्थान के आसपास के विभिन्न वर्गों के लोगों के बीच सद्भाव पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता। घटना का। हालाँकि, लोगों के मन में दहशत पैदा करने या समाज के किसी भी वर्ग के बीच सद्भाव पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली ऐसी कोई घटना सामने नहीं आई। किसी व्यक्ति की मौत का कथित कृत्य केवल आरोपी-अपीलकर्ताओं द्वारा हथियारों से किया गया हमला था। मृतक पर जिसने बाद में चोटों के कारण दम तोड़ दिया।

14. हमने देखा है कि ए-6 के संबंध में टीएडीए की धारा 20-ए(2) के तहत मंजूरी पीडब्लू-29 द्वारा 16.09.1998 को दी गई थी, जिसमें उसके खिलाफ जांच में समय लगने के कारण देरी हुई थी। हमारी सुविचारित राय में, ऊपर उल्लिखित कारणों से यह भी गैरकानूनी है। इसके अलावा, पीडब्लू-30 की जिरह भी दिमाग के गैर-प्रयोग को प्रतिबिंबित कर रही है। जब विशेष रूप से आरोपी-अपीलकर्ताओं के अलुम्मा संगठन के साथ संबंधों के बारे में बताने के बाद, उसके द्वारा यह दर्शाया गया था कि उसने यह दिखाने के लिए कोई सबूत या दस्तावेज एकत्र नहीं किया था। आरोपी उस संगठन के थे. हमारी सुविचारित राय में, उक्त प्रतिबंध, जो इन गवाहों के बयानों से साबित नहीं हुए हैं, महाराष्ट्र राज्य बनाम महेश जी जैन, (2013) 8 एससीसी 119, और कूथा पेरुमल बनाम राज्य, (2011) 1 एससीसी 491 मामले में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून के आदेश के अनुसार नहीं हैं।

15. अभिलेखों को देखने के बाद, हमें ऐसा प्रतीत होता है कि अभियुक्त-अपीलकर्ताओं के मन में द्वेष था क्योंकि मृतक विभिन्न स्थानों पर विनयगा चतुर्थी समारोह आयोजित करता था और मुसलमानों और इस्लाम की आलोचना करता था जिसमें मृतक द्वारा एक सार्वजनिक नोटिस शामिल था जिसमें उसने कहा था मदुरै शहर की सुरक्षा की मांग की, जिसके अनुसार मृतक को, पाकिस्तान द्वारा जासूसी के लिए आधार के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा था गतिविधि। इस सार्वजनिक नोटिस को जारी करने को पीडब्लू-11, ए.आर. कालिदासन. द्वारा सिद्ध किया गया था। यहां अपीलकर्ताओं द्वारा पथराव के उदाहरण थे। पीडब्लू-10 के साक्ष्य से साबित हुआ, जैसा कि पीडब्लू-13 के बयान से पुष्ट होता है।

16. प्रतिवादी-सीबीआई के विद्वान वकील श्री पी.के. डे ने हमारा ध्यान करतार सिंह बनाम पंजाब राज्य, 1994 (3) एससीसी 569 में इस न्यायालय के फैसले की ओर आकर्षित किया है, जिसमें पैरा 451 में, इस न्यायालय ने कहा था:

"धारा में निर्दिष्ट हथियारों और गोला-बारूद के कब्जे को ही गंभीर अपराध बना दिया गया है। यह प्रकृति में बहुत गंभीर है और प्रभाव में भी गंभीर है क्योंकि इसके परिणामस्वरूप किसी व्यक्ति पर आतंकवादी या आतंकवादी गतिविधि से जुड़े या संबंध के बावजूद मुकदमा चलाया जाता है। एक तुलना धारा 3 और 4 के साथ यह धारा इसमें निहित मनमानी को दर्शाती है। धारा 3 तब लागू होती है जब कोई व्यक्ति न केवल सरकार को डराने या लोगों में आतंक पैदा करने आदि का इरादा रखता है, बल्कि वह हथियारों और गोला-बारूद का उपयोग करता है जिसके परिणामस्वरूप मृत्यु हो जाती है या होने की संभावना होती है। मौत और संपत्ति आदि को नुकसान पहुंचाना। दूसरे शब्दों में, कोई व्यक्ति आतंकवादी बन जाता है या आतंकवादी गतिविधि का दोषी होता है जब इरादा, कार्रवाई और परिणाम तीनों तत्व मौजूद पाए जाते हैं। इसी तरह धारा 4 उन गतिविधियों पर लागू होती है जो बाधित करने के लिए निर्देशित होती हैं देश की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता। इस प्रकार एक आतंकवादी या विघटनकारी और धारा में उल्लिखित किसी भी हथियार और गोला-बारूद रखने वाले व्यक्ति को एक बराबर रखा गया है। धारा 3 और 4 में अपराध किए जाने पर होता है जबकि धारा 5 में यह केवल कब्जे पर स्थापित होता है। यहां तक कि धारा 3 की उपधारा (3) के तहत भी यदि कोई व्यक्ति किसी आतंकवादी की सहायता करता है या उसके साथ संचार करता है तो उस पर अपराध को बढ़ावा देने के लिए मुकदमा चलाया जा सकता है। 1993 के अधिनियम 43 द्वारा धारा 3 में सम्मिलित उपधारा (5) और (6) में यह भी कहा गया है कि किसी व्यक्ति पर

केवल तभी मुकदमा चलाया जा सकता है जब वह किसी आतंकवादी गिरोह या आतंकवादी संगठन आदि का सदस्य पाया जाता है। इसलिए, अधिनियम, धारा 3 और 4 के तहत अपराधों के लिए आतंकवादी या विघटनकारी और अन्य के खिलाफ मुकदमा चलाने की कल्पना केवल तभी की जाती है जब वे इससे जुड़े या संबंधित हों। यह अधिनियम के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए है। कानून को बरकरार रखा गया है क्योंकि विधायिका ऐसे अपराध के संबंध में कानून बनाने में सक्षम है जो अन्यथा सातवीं अनुसूची की सूची II में किसी भी प्रविष्टि द्वारा कवर नहीं किया गया है। अपराध की परिभाषा, जैसा कि पहले चर्चा की गई है, अधिनियम की धारा 3 और 4 में निहित है और यह सच है कि अपराध को परिभाषित करते समय विधायिका ऐसे प्रावधान करने के लिए स्वतंत्र है जो कानून के उद्देश्य को पूरा कर सके और व्यापक दृष्टिकोण से कोई यह कह सकता है कि ऐसे हथियारों का कब्ज़ा, जिनके उपयोग से आतंकवादी हो सकते हैं गतिविधि को निवारक या निवारक प्रावधान के रूप में अपराधों में से एक के रूप में लिया जाना चाहिए। फिर भी दोनों के बीच कुछ अंतर-संबंध अवश्य होना चाहिए, भले ही वह कितना भी दूर क्यों न हो। प्रावधानों की कठोरता स्पष्ट है क्योंकि किसी व्यक्ति पर मुकदमा चलाने के लिए अधिनियम के वे सभी प्रावधान, जिनमें संपत्ति की जब्ती, ओलावृष्टि से इनकार आदि शामिल हैं, किसी भी हथियार और गोला-बारूद रखने के आरोपी व्यक्ति पर लागू होते हैं, जिस पर किसी अपराध के लिए आरोप लगाया जाता है। अधिनियम की धारा 3 और 4. इसमें कोई संदेह नहीं है कि किसी के पास ऐसे हथियार और

गोला-बारूद रखने का औचित्य नहीं है जैसा कि धारा 5 में बताया गया है, लेकिन अनुचित कब्ज़ा किसी व्यक्ति को आतंकवादी या विघटनकारी नहीं बनाता है। यहां तक कि आयरलैंड आपातकालीन प्रावधान अधिनियम, 1978 के तहत भी, जिस पर विद्वानों द्वारा बहुत अधिक भरोसा किया गया था। अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के पास धारा 5 जैसा कोई कठोर प्रावधान नहीं है। चूंकि किसी आतंकवादी और विघटनकारी या आतंकवादी कृत्य या विघटनकारी कृत्य पर मूल और प्रक्रियात्मक कानून दोनों लागू होते हैं, इसलिए मेरी राय में, यह आवश्यक है कि इस धारा को लागू किया जाए। मनमानेपन के हमले से मुक्त रहें, केवल तभी लागू किया जा सकता है जब यह दिखाने के लिए कुछ सामग्री हो कि जिस व्यक्ति के पास हथियार थे, उसका इरादा इसका इस्तेमाल आतंकवादी या विघटनकारी गतिविधि के लिए करना था या यह एक हथियार और गोला-बारूद था जिसका वास्तव में उपयोग किया गया था।"

(जोर दिया गया)

17. उन्होंने गिरधारी परमानंद वधवा बनाम महाराष्ट्र राज्य, (1996) 11 एससीसी 179), के मामले में इस न्यायालय के फैसले पर भी भरोसा किया। जिसमें यह प्रतिपादित किया गया था कि एक अपराध, भले ही अत्यधिक क्रूरता के साथ किया गया हो, टाडा की धारा 3(1) के अर्थ में "आतंकवादी गतिविधि" नहीं हो सकता है। "आतंकवादी गतिविधि" बनाने के लिए, गतिविधि का उद्देश्य लोगों या लोगों के एक वर्ग में आतंक फैलाना या धारा 3(1) में निर्दिष्ट अन्य परिणाम लाना होना चाहिए। आतंकवादी गतिविधि किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के खिलाफ की गई गैरकानूनी गतिविधि या अपराध तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य लोगों या लोगों के एक वर्ग के

मन में सार्वजनिक व्यवस्था, सार्वजनिक शांति और शांति, सामाजिक और सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ना, परेशान करना या आतंक पैदा करना है। सार्वजनिक प्रशासन को अस्थिर करना और देश की सुरक्षा और अखंडता को खतरे में डालना।

18. इसलिए, विधायी प्रयास के अभाव में, यह परिभाषित करने के लिए एक राय प्रदान करना हमारे लिए बहुत खतरनाक होगा कि कोई गतिविधि आतंकवादी गतिविधि की परिभाषा में आती है या नहीं। आख़िरकार किसी भी क़ानून को लागू करने के पीछे विधायी मंशा प्रबल होगी। इस न्यायालय ने हितेंद्र विष्णु ठाकुर और अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य एवं अन्य, (1994) 4 एससीसी 602, के मामले में न्यायमूर्ति डॉ. ए.एस. आनंद के शब्दों में यह राय दी थी।

> "7. आतंकवाद" बढ़ती अराजकता और हिंसा के पंथ की अभिव्यक्तियों में से एक है। हिंसा और अपराध स्थापित व्यवस्था के लिए ख़तरा हैं और सभ्य समाज के ख़िलाफ़ विद्रोह हैं। "आतंकवाद को टीएडीए के तहत परिभाषित नहीं किया गया है और न ही 'आतंकवाद' की सटीक परिभाषा देना या यह बताना संभव है कि 'आतंकवाद' क्या है। इसे हिंसा के उपयोग के रूप में वर्णित करना संभव हो सकता है जब इसका सबसे महत्वपूर्ण परिणाम केवल हिंसा नहीं है।" पीड़ित की शारीरिक और मानसिक क्षति होती है लेकिन इसका लंबे समय तक मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ता है या समग्र रूप से समाज पर पड़ने की संभावना होती है। इस प्रक्रिया में मृत्यु, चोट, या संपत्ति का विनाश या यहां तक कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हनन भी हो सकता है लेकिन सीमा और इच्छित आतंकवादी गतिविधि की पहुंच देश के सामान्य दंड कानून के तहत दंडित होने योग्य एक सामान्य अपराध के प्रभाव से परे है और इसका मुख्य उद्देश्य सरकार को अपमानित करना या

समाज के सद्भाव को बिगाड़ना या लोगों और समाज को "आतंकित" करना है। और न केवल सीधे तौर पर उन पर हमला किया गया, बल्कि समाज की गति, शांति और शांति को बाधित करने और भय और असुरक्षा की भावना पैदा करने के लिए भी हमला किया गया। एक 'आतंकवादी' गतिविधि केवल कानून और व्यवस्था या सार्वजनिक व्यवस्था में गड़बड़ी पैदा करने से उत्पन्न नहीं होती है। इच्छित गतिविधि का परिणाम ऐसा होना चाहिए कि यह सामान्य दंड कानून के तहत इससे निपटने के लिए सामान्य कानून प्रवर्तन एजेंसियों की क्षमता से परे हो। अनुभव ने हमें दिखाया है कि आतंकवाद आम तौर पर लोगों या उसके किसी भी वर्ग के लोगों के मन में भय और असहायता पैदा करके सत्ता हासिल करने या नियंत्रण बनाए रखने का एक प्रयास है और यह पूरी तरह से असामान्य घटना है। 'आतंकवाद' को हिंसा के अन्य रूपों से क्या अलग करता है। इसलिए, यह जबरदस्ती डराने-धमकाने का जानबूझकर और व्यवस्थित उपयोग प्रतीत होता है। अधिकांशतः, आज एक कट्टर अपराधी स्थिति का लाभ उठाता है और 'आतंकवाद' का लबादा पहनकर समाज में अपने लिए स्वीकार्यता और सम्मान हासिल करना चाहता है क्योंकि दुर्भाग्य से उग्रवाद से प्रभावित राज्यों में, एक 'आतंकवादी' को पेश किया जाता है। अपने समूह द्वारा और अक्सर गुमराह युवाओं द्वारा भी एक नायक के रूप में। इसलिए, ऐसे अपराधी के साथ व्यवहार करना और उसके साथ देश के दंड कानून के तहत सामान्य अदालतों में मुकदमा चलाने में सक्षम एक सामान्य अपराधी से अलग व्यवहार करना आवश्यक है। भले ही एक 'आतंकवादी' और एक सामान्य अपराधी

द्वारा किया गया अपराध एक हद तक ओवरलैप हो सकता है, लेकिन विधायिका का यह इरादा नहीं है कि हर अपराधी पर टाडा के तहत मुकदमा चलाया जाए, जहां उसकी गतिविधि का नतीजा इससे आगे न बढ़े। सामान्य आपराधिक गतिविधि की सामान्य सीमाएँ। प्रत्येक आतंकवादी' अपराधी हो सकता है लेकिन प्रत्येक अपराधी को 'आतंकवादी' का लेबल केवल टाडा के अधिक कठोर प्रावधानों को लागू करने के लिए नहीं दिया जा सकता है। टीएडीए को लागू करने के लिए आपराधिक गतिविधि को अधिनियम की धारा 3(1) के अनुसार अपेक्षित इरादे से ऐसे हथियारों का उपयोग करके प्रतिबद्ध किया जाना चाहिए जैसा कि धारा 3(1) में गिना गया है और जिसके परिणामस्वरूप या होने की संभावना है उक्त धारा में उल्लिखित अपराध।"

19. इसलिए, हम यह स्पष्ट रूप से स्पष्ट कर देंगे कि ये भरोसेमंद मामले प्रतिवादी को लोगों के मन में आतंक पैदा करने या उन पर आतंक पैदा करने के इरादे के अभाव में टाडा के प्रावधानों के तहत मामला बनाने में मदद नहीं करते हैं। इसलिए, हमारी सुविचारित राय में, वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में पुलिस अधीक्षक (पीडब्लू-26) और आईजी, सीबीआई (पीडब्लू-28) द्वारा दी गई मंजूरी, निर्धारित आवश्यकताओं के अनुपालन के अभाव में पूरी तरह से अमान्य थी। टाडा की धारा 20-ए के तहत। हालाँकि, यह उचित रूप से कहा जा सकता है कि वर्तमान मामले में पूर्व मंजूरी कानून की नजर में खराब थी, फिर भी, यह नहीं कहा जा सकता है कि टाडा के तहत आरोपी-अपीलकर्ताओं के खिलाफ पूरी कार्यवाही, अशरफखान उर्फ बाबू मुन्नेखां पठान और अन्य बनाम गुजरात राज्य, (2012) 11 एससीसी 606, के मामले में फैसले के आलोक में खराब हो गई थी। जिसमें इस न्यायालय ने कहा:

"33. अब हम राज्य द्वारा दिए गए निवेदन पर विचार करने के लिए आगे बढ़ते हैं कि धारा 20-ए(1) का अनुपालन नहीं किया गया है। जिला पुलिस अधीक्षक की मंजूरी का अभाव, संहिता की धारा 465 के तहत एक इलाज योग्य दोष है। हमें यह मानने में तनिक भी झिझक नहीं है कि टाडा के तहत निर्दिष्ट न्यायालय द्वारा किसी अपराध की सुनवाई में संहिता की धारा 465 लागू होगी। यह टाडा की धारा 14 (3) से स्पष्ट होगा जो इस प्रकार है:

14. नामित न्यायालयों की प्रक्रिया और शक्तियां.-

(1)-(2)

(3) इस अधिनियम के अन्य प्रावधानों के अधीन, एक नामित न्यायालय के पास, किसी भी अपराध की सुनवाई के प्रयोजन के लिए, सत्र न्यायालय की सभी शक्तियां होंगी और वह ऐसे अपराध की सुनवाई करेगा जैसे कि वह अब तक एक सत्र न्यायालय था। जैसा कि सत्र न्यायालय के समक्ष मुकदमे के लिए संहिता में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार हो सकता है।'

34. उपरोक्त प्रावधान को स्पष्ट रूप से पढ़ने से यह स्पष्ट है कि मुकदमे के प्रयोजन के लिए नामित न्यायालय एक सत्र न्यायालय है। इसमें सत्र न्यायालय की सभी शक्तियां हैं और टाडा के तहत मामले की सुनवाई करते समय, नामित न्यायालय को सत्र न्यायालय के समक्ष मुकदमे के लिए कैड में निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना होता है। संहिता की धारा 465, जो अध्याय 35 में आती है, सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय मामलों को भी कवर करती है। इसलिए, अभियोजन

पक्ष संहिता की धारा 465 का सहारा ले सकता है। लेकिन संहिता की धारा 465 सभी त्रुटि, चूक या अनियमितता के लिए रामबाण नहीं होगी। पुलिस अधीक्षक द्वारा टाडा के तहत मामले के पंजीकरण के लिए पूर्व मंजूरी देने में चूक उस तरह की चूक नहीं है जो संहिता की धारा 465 के तहत आती है। यह एक ऐसा दोष है जो मामले की जड़ तक जाता है और यह इलाज योग्य दोषों में से एक नहीं है।"

20. इसलिए हमारी यह सुविचारित राय है कि अवैध मंजूरी आदेश के परिणामस्वरूप टाडा अधिनियम के तहत अभियोजन के लिए आपराधिक कार्यवाही पूरी तरह से दूषित हो गई है। यह कहना पर्याप्त होगा कि टाडा अधिनियम के तहत विद्वान न्यायालय ने मामले का संज्ञान लेने में घोर गलती की है।

21. अपीलकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील श्री एम. करपगा विनायगम ने सक्षम प्राधिकारी द्वारा दी गई मंजूरी को चुनौती देने के अलावा तीन मुख्य प्रस्तुतियाँ दीं। पहले पैराग्राफ में पहले ही चर्चा की जा चुकी है। उन्होंने कहा कि चश्मदीद गवाह और पीडब्लू-7 विश्वसनीय नहीं हैं। उन्होंने आगे कहा कि ए-1 का कबूलनामा स्वैच्छिक नहीं है और इसमें महत्वपूर्ण गवाहों की जांच नहीं की गई है। अपने तर्कों के साथ निष्कर्ष निकालते हुए वह कहेंगे कि पहचान परेड एक दिखावा है और जांच अधिकारियों पीडब्लू-2, पीडब्लू-24 और पीडब्लू-30 के बयानों में कमजोरियाँ हैं।

22. हमने रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्यों की फिर से सराहना की है और श्री पी.के. डे प्रतिवादी-सीबीआई की ओर से उपस्थित विद्वान वकील द्वारा दिए गए तर्कों पर विचार किया है। हालाँकि हमें विद्वान नामित न्यायालय द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण को पूरी तरह से स्वीकार करने में थोड़ी कठिनाई होती है, क्योंकि यह कई उल्लेखनीय तथ्यों से

उत्पन्न होता है, लेकिन इस बात पर विवाद नहीं किया जा सकता है कि मृतक को उसके घर के प्रवेश द्वार पर मार दिया गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्रदर्श पी-14 है, जिसे पीडब्ल्यू-15 डॉ. त्यागराजन द्वारा विधिवत साबित किया गया था ने यह भी उल्लेख किया कि मृत्यु का कारण 10.10.1994 को सुबह 5 बजे के आसपास मृतक को कई बार काटने और चाकू से चोट लगने के कारण सदमा और रक्तस्राव था। हमने देखा है कि आरोपी-अपीलकर्ताओं की पहचान के लिए पीडब्लू-1 को कभी नहीं बुलाया गया था।

23. वर्तमान मामले में परीक्षण पहचान परेड की विश्वसनीयता के सवाल पर, जब माना गया कि आरोपियों को पहले ही अखबार के माध्यम से देखा जा चुका है, हम इस प्रश्न के उत्तर पर आने से पहले इस न्यायालय के कुछ निर्णयों पर जोर देते हैं। यह न्यायालय सुरेश चंद्र बाहरी बनाम बिहार राज्य, 1995 समर्थन (1) एससीसी 80, के मामले में है।अभिनिर्धारित किया है:

> "78....इस दृष्टिकोण से यह जांच एजेंसी और आरोपी दोनों के लिए और न्याय के उचित प्रशासन के लिए बहुत महत्वपूर्ण बात है कि गिरफ्तारी के बाद ऐसी पहचान बिना टाले और अनुचित देरी के की जाती है। आरोपी और सभी आवश्यक सावधानियां और सुरक्षा उपाय प्रभावी ढंग से उठाए गए ताकि वास्तविक अपराधी को दंडित करने के लिए जांच सही दिशा में आगे बढ़े। इसके अलावा, यह संबंधित गवाह के लिए भी निष्पक्ष होगा जो आरोपी के लिए अजनबी था क्योंकि उसमें घटना के बाद उसकी याददाश्त कमजोर होने की संभावना कम हो जाती है और उसे घटना के बाद जल्द से जल्द कथित अपराधी की पहचान करने की आवश्यकता होती है। केवल इस पाठ्यक्रम को अपनाने से ही आरोपी के साथ-साथ दोनों को न्याय और निष्पक्ष खेल

का आश्वासन दिया जा सकता है। अभियोजन पक्ष के लिए। लेकिन जब अभियुक्त या अपराधी पर मुकदमा चल रहा हो तो स्थिति भिन्न हो सकती है एक बार नहीं बल्कि कई बार देखा गया था। समय और स्थान के अलग-अलग बिंदु जो वास्तव में टीआई परेड की आवश्यकता को दूर कर सकते हैं।"

24. हम अपीलकर्ताओं के विद्वान वरिष्ठ वकील के इस तर्क को स्वीकार करते हैं कि परीक्षण पहचान परेड एक दिखावा था क्योंकि आरोपियों की तस्वीरें अखबार में प्रकाशित होने के बाद, पहचान परेड जो कि बहुत कमजोर सबूत है, नहीं होनी चाहिए थी आयोजित किया गया।

25. इस निर्णय को समाप्त करने से पहले, सबसे महत्वपूर्ण कारक पर विचार करना आवश्यक होगा जिस पर प्रतिवादी के विद्वान वकील ने हमारा ध्यान आकर्षित किया था, अर्थात, अभियुक्तों का कबूलनामा और साजिश का खुलासा और उसके बाद सबूतों की बरामदगी। अब तक दर्ज की गई टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए, राज्य (एनसीटी दिल्ली) बनाम में इस न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले पर जोर दिया गया है। नवजोत संधू, (2005) 11 एससीसी 600, आवश्यक है जिसमें यह देखा गया:

"28. पकाला नारायण स्वामी वा. सम्राट के प्रिवी काउंसिल निर्णय में, एआईआर 1939 पीसी 47, लॉर्ड एटकिन ने निम्नलिखित शब्दों में 'स्वीकारोक्ति' अभिव्यक्ति के अर्थ और अभिप्राय को स्पष्ट किया:

"[ए] स्वीकारोक्ति में या तो अपराध के संदर्भ में स्वीकारोक्ति होनी चाहिए, या किसी भी दर पर काफी हद तक उन सभी तथ्यों को स्वीकार किया जाना चाहिए जो अपराध का गठन करते हैं। एक गंभीर रूप से दोषी ठहराने वाले तथ्य की स्वीकृति, यहां तक कि निर्णायक

रूप से दोषी ठहराने वाला तथ्य भी अपने आप में एक स्वीकारोक्ति नहीं है.. ''

29. कन्फ़ेशन को अत्यधिक विश्वसनीय माना जाता है क्योंकि कोई भी तर्कसंगत व्यक्ति अपने हित के विरुद्ध स्वीकारोक्ति नहीं करेगा जब तक कि उसकी अंतरात्मा उसे सच बताने के लिए प्रेरित न करे। "जानबूझकर और स्वैच्छिक अपराध स्वीकारोक्ति, अगर स्पष्ट रूप से साबित हो जाए तो कानून में सबसे प्रभावशाली सबूतों में से एक है"। (टेलर्स ट्रीटीज़ ऑन द लॉ ऑफ़ एविडेंस खंड 1 देखें)। हालाँकि, किसी स्वीकारोक्ति पर कार्रवाई करने से पहले अदालत को संतुष्ट होना चाहिए कि यह स्वतंत्र रूप से और स्वेच्छा से किया गया था। लाभ, पुरस्कार या प्रतिरक्षा की आशा या वादे से या बलपूर्वक या हिंसा या हिंसा की धमकियों से प्रेरित भय से स्वीकारोक्ति, स्वीकारोक्ति के निर्माता के खिलाफ सबूत नहीं बन सकती है। स्वीकारोक्ति की प्रकृति और परिणामों की पूरी जानकारी के साथ स्वीकारोक्ति की जानी चाहिए। यदि अदालत को कोई उचित संदेह है कि ये सामग्रियां संतुष्ट नहीं हैं, तो अदालत को स्वीकारोक्ति पर विचार करने से बचना चाहिए।

इसी प्रकार, स्वीकारोक्ति दर्ज करने वाले प्राधिकारी, चाहे वह मजिस्ट्रेट हो या पूर्व-परीक्षण चरण में कोई अन्य वैधानिक पदाधिकारी, को इस मुद्दे पर खुद को संबोधित करना चाहिए कि क्या अभियुक्त भय, दबाव या आशा से मुक्त माहौल में बयान देने के लिए आगे आया है। प्राधिकारी व्यक्तियों द्वारा प्रेरित किसी लाभ या पुरस्कार से। पुलिस हिरासत में अभियुक्तों के भय और घबराहट, चिंता और निराशा की स्थिति में घिरे होने की कठोर वास्तविकता को पहचानते हुए, साक्ष्य

अधिनियम ने पुलिस अधिकारी को दिए गए कबूलनामे की स्वीकार्यता को बाहर कर दिया है।

इस विश्वसनीय निर्णय के बाद के पैराग्राफ में इस न्यायालय ने आगे कहा:

"32. किसी व्यक्ति को दोषी ठहराने के लिए मुख्य रूप से स्वीकारोक्ति या वापस लिए गए बयान के आलोक में न्यायालय का कानूनी दृष्टिकोण क्या होना चाहिए, इसे भारत बनाम यूपी राज्य [1971 (3) एससीसी 950) में संक्षेप में प्रस्तुत किया गया है। हिदायतुल्ला, सी.जे., ने तीन-न्यायाधीशों की पीठ के लिए बोलते हुए इस प्रकार कहा:

इकबालिया बयान पर कार्रवाई की जा सकती है यदि अदालत संतुष्ट हो कि वे स्वैच्छिक हैं और वे सच हैं। स्वीकारोक्ति की स्वैच्छिक प्रकृति इस बात पर निर्भर करती है कि क्या कोई धमकी, प्रलोभन या वादा था और इसकी सच्चाई पूरे अभियोजन मामले के संदर्भ में आंकी जाती है। स्वीकारोक्ति सिद्ध तथ्यों में फिट होनी चाहिए और उनके विपरीत नहीं होनी चाहिए। जब स्वीकारोक्ति का स्वैच्छिक चरित्र और उसकी सच्चाई स्वीकार कर ली जाती है, तो उस पर भरोसा करना सुरक्षित होता है। वास्तव में एक स्वीकारोक्ति, यदि यह स्वैच्छिक और सच्ची है और किसी प्रलोभन या धमकी या वादे के तहत नहीं की गई है, तो यह निर्माता के खिलाफ सबूत का सबसे पेटेंट टुकड़ा है। हालाँकि, वापस लिया गया स्वीकारोक्ति थोड़ा अलग स्तर पर है। जैसा कि प्रिवी काउंसिल ने एक बार कहा था, भारत में यह नियम है कि किसी अपराध की स्वीकारोक्ति की जाए और बाद में उसे वापस ले

लिया जाए। एक अदालत वापस ली गई स्वीकारोक्ति को ध्यान में रख सकती है, लेकिन उसे स्वीकारोक्ति के कारणों के साथ-साथ उसकी वापसी के कारणों को भी देखना चाहिए, और यह निर्धारित करने के लिए दोनों का मूल्यांकन करना चाहिए कि क्या वापसी स्वीकारोक्ति की स्वैच्छिक प्रकृति को प्रभावित करती है या नहीं। यदि अदालत इस बात से संतुष्ट है कि बाद में विचार-विमर्श या सलाह के कारण इसे वापस ले लिया गया है, तो मामले में सामान्य तथ्य साबित होने पर अदालत के फैसले को वापस नहीं लिया जा सकता है और स्वीकारोक्ति की प्रकृति और इसके करने और वापस लेने की परिस्थितियाँ इसके उपयोगकर्ता की गारंटी देती हैं। फिर भी, अदालतें अभियुक्त के अपराध के बारे में किसी अन्य स्रोत से आश्वासन प्राप्त किए बिना वापस ली गई स्वीकारोक्ति पर कार्रवाई नहीं करती हैं। इसलिए, यह कहा जा सकता है कि स्वेच्छा से की गई सच्ची स्वीकारोक्ति को पुष्ट करने के लिए मामूली सबूतों के साथ कार्रवाई की जा सकती है, लेकिन मुकरने वाली स्वीकारोक्ति के लिए सामान्य आश्वासन की आवश्यकता होती है कि मुकरना बाद में सोचा गया था और पहले वाला बयान सच था। यह इस न्यायालय द्वारा सुब्रमण्यम गौंडेन बनाम मद्रास राज्य (1958 एससीआर 428) में रिपोर्ट किए गए एक पुराने मामले में निर्धारित किया गया था।"

26. हमारी यह सुविचारित राय है कि ए-1 और ए-6 की स्वीकारोक्ति अनैच्छिक है क्योंकि उन्हें सीबीआई की तत्काल उच्च सुरक्षा वाली हिरासत में लिया गया था और गैर-स्वैच्छिक स्वीकारोक्ति दोषसिद्धि का आधार नहीं बन सकती। हम अशरफखान के मामले (सुप्रा) में इस न्यायालय द्वारा की गई एक और टिप्पणी पर जोर देना चाहेंगे:

"41. हमने टाडा की धारा 20-ए(1) का अनुपालन न करने के कारण आरोपी की सजा को कमजोर माना है और इस प्रकार, शस्त्र अधिनियम और के तहत सजा को बनाए रखना कानून में स्वीकार्य हो सकता है। विस्फोटक पदार्थ अधिनियम लेकिन यह तभी संभव होगा जब उन आरोपों को स्थापित करने के लिए कानूनी रूप से स्वीकार्य साक्ष्य होंगे। नामित न्यायालय ने शस्त्र अधिनियम और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के तहत अपराधों के लिए आरोपियों को दोषी ठहराने के लिए केवल टाडा के तहत दर्ज किए गए बयानों पर भरोसा किया है। हमारे निष्कर्ष से पता चलता है कि टाडा की धारा 20-ए (1) के तहत पूर्व अनुमोदन की अनिवार्य आवश्यकता का पालन न करने के कारण उनकी सजा को रद्द कर दिया गया है। उपरोक्त अधिनियमों के तहत अपराध स्थापित करने के लिए दर्ज किए गए बयानों को नहीं देखा जा सकता है। इसलिए, शस्त्र अधिनियम की धारा 7 और 25(1-ए) और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 4, 5 और 6 के तहत अभियुक्तों की दोषसिद्धि को भी बरकरार नहीं रखा जा सकता है।"

27. हम अशरफखान के मामले (सुप्रा) में इस न्यायालय की टिप्पणी को भी दोहराना चाहेंगे जो इस प्रकार है:

"44. मामले के तथ्य शोकपूर्ण प्रतिबिंब उत्पन्न कर सकते हैं कि कैसे जांच एजेंसी द्वारा आरोप लगाया गया था। आतंकवाद को रोकने और दोषसिद्धि सुनिश्चित करने का कर्तव्य उस चीज़ से विफल हो गया है जिसे आम तौर पर तकनीकी त्रुटि कहा जाता है। हम इस बात पर जोर देते हैं और दोहराना जरूरी समझते हैं कि आतंकवाद से समुदाय को होने वाली

बुराई की गंभीरता, संविधान और कानूनों द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अलावा, व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर हमला करने के लिए कभी भी पर्याप्त कारण नहीं दे सकती है।"

28. ऊपर उद्धृत निर्णयों और रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री के आलोक में, हमें यह मानने में कोई झिझक नहीं है कि वर्तमान मामले में पूरी कार्यवाही दूषित थी। इसलिए, नामित न्यायालय द्वारा पारित दोषसिद्धि और सजा के आदेश को रद्द कर दिया गया है। यदि किसी अन्य मामले में आवश्यक न हो तो अपीलकर्ताओं को तुरंत रिहा किया जाए।

29. परिणामस्वरूप, तदनुसार, अभियुक्त-अपीलकर्ताओं द्वारा दायर अपीलें स्वीकार की जाती हैं।

निधि जैन अपील की अनुमति

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल '**सुवास**' की सहायता से अनुवादक मयंक चौधरी अधिवक्ता द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण : यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।